tidal sea waves in the State of Gujarat, particularly in Porbandar, Veraval and Jamnagar district;

(b) if so, the expenditure likely to be involved therein;

(c) whether any other agencies have also offered to finance the projects;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) Yes, Sir, a proposal for the generation of about 900 MW power by harnessing Tidal Energy in the Gulf of Kachchh in Gujarat has been under consideration. The techno-economic feasibility report by Central Electricity Authority/ National Hydro Electric Power Corporation Ltd. has estimated the project cost to be about Rs. 6000.00 crores.

(c) No other agency has offered to finance the above project.

(d) Does not arise.

(e) In view of the very high capital cost, low plant load factor of only abou 21 per cent and change in timing of tidal peak and therefore power output every day, the project is not considered to be economically viable vis-a-vis other means of power currently available. This is the apparent reason for no other agency having offered to finance the project.

मध्य प्रदेश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

2415. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के तहत अब तक कार्य शुरु कर दिया गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं ?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई० आर०ई०पी०) ब्लाक को आयोजना की एक इकाई के रूप में लेकर कार्यान्वित किया जाता है । वर्ष 1993-94 तक आई०आर०ई०पी० के तहत मध्य प्रदेश के 37 ब्लाकों को शामिल किया गया है । शामिल किए गए ब्लाकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । (लाई ब्रेडिए)

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई० आई०ई०पी० योजना के तहत राज्य और जिला/ ब्लाक स्तर पर आई०आर०ई०पी० कक्षों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को क्रमश: 30.65 लाख रुपए, 36 41 लाख रुपए और 35.70 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी ।

(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य में एक राज्य स्तर के और 37 ब्लाक स्तर के आई०आर०ई०पी० कक्षों का सृजन किया गया है । इसके अलावा, एक राज्य स्तर के और 12 जिला स्तर की तकनीकी सहायता इकाइयों की भी स्थापना की गई है ।

विवरण

मध्य प्रदेश में आई० आर० ई० पी० के तहत ब्लाकों की सूची

संख्या	ब्लाक का नाम	जिला
1.	केसला	होशंगाबाद
2.	कोंडवानी	धार
3.	कोंडागांव	बस्तर
4.	दिनदोरी	मंडला
5.	सोहकपुर	शाहडोल

संख्या	ब्लाक का नाम	जिला
6.	बेतुल	बेतुल
7.	धर्मजयगढ़	रायगढ़
8.	अम्बिकापुर	सरगुजा
9.	झाबुआ	झाबुआ
10.	गोटगांव	नरसिंहपुर
11.	विजयराघवगढ़	जबलपुर
12.	सियौनी	सियौनी
13.	अमरपाटन	सतना
14.	सिद्धि	सिद्धि
15.	शाहनगर	पन्ना
16.	कोटा	बिलासपुर
17.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
18.	अब्दुल्लागंज	रायसेन
19.	बागली	देवास
20.	महो	इन्दौर
21.	बैरासिया	भोपाल
22.	गंजबसेदा	विदिशा
23.	नेहोरा	मेहोर
24.	नरसिंहगढ़	राजगढ़
25.	राहतगढ़	सागर
26.	दमोह	दमोह
27.	छतरपुर	छतरपुर
28.	कांटजी	बाल घाट
29.	दुरा	दुर्ग
30.	अभानपुर	रायपुर
31.	घाटीगांव	ग्वालियर
32.	पिछौरी	शिवपुरी
33.	चंदेरी	गुना
34.	कालपिप्पल	शाजपुर
35.	महिदपुर	उज्जैन
36.	मनासा	मन्दसौर
37.	बाघवा	खारगान

सौर ऊर्जा की सहायता से सिंचाई

2416. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेषतया गुजरात में सौर ऊर्जा की सहायता से सिंचाई की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या फ्रांस ने इन प्रयोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(घ) यदि हां, तो वे निबंधन और शर्तें क्या हैं जिनके तहत सहायता प्रदान की गई है ; और

(ङ) कार्यान्वित की जाने वाली प्रायोगिक परियोजनायें किस प्रकार की है ?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने कृषि और संबंधित उपयोगों के लिए 200-1300 डब्ल्यू० पी० के बीच पी०वी० अरे क्षमता की 1000 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों के आबंटन के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान एक प्रदर्शन परियोजना शुरु की थी । परियोजना को बाजार अभिविन्यास के रूप में कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सौंपी गई थी । इस योजना के तहत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वित्तीय सहायता से गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से छठी और सातवीं योजना के दौरान माइक्रो सिंचाई सहित विभिन्न जल पम्पन आवश्यकताओं के लिए गुजरात में 300-360 डब्ल्यू०पी० की 98 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों स्थापित की गई हैं ।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ गांवों में 50 सौर